बुधवार, 29 जुलाई, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

33 साल की उम्र में सारांश जैन को भारतीय टीम से आया बुलावा

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

'बंटवारा 1947' का दमदार ट्रेलर रिलीज

Page-05

पेपर लीक बिल पर लोकसभा में घमासान

BJP ने संशोधन को बताया 'जीरो टॉलरेंस' की नीति

- लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पर तीखी बहस हुई।
- कांग्रेस, सपा, टीएमसी और डीएमके समेत विपक्षी दलों ने पेपर लीक, छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई और शिक्षा व्यवस्था को

लोकसभा में मंगलवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। केंद्र सरकार ने इस संशोधन विधेयक को परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और पेपर लीक माफिया पर कड़ी कार्रवाई का बड़ा कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे सरकार की नाकामी छिपाने की कोशिश करार दिया।चर्चा की शुरुआत केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की। उन्होंने कहा कि सरकार परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रस्तावित संशोधन में पेपर लीक और परीक्षा में संगठित धांधली करने वालों के खिलाफ 10 साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। सरकार का दावा है कि नया कानून केवल नकल करने वालों पर नहीं, बल्कि पूरे पेपर लीक नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।उधर, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने छात्रों के आंदोलन और कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग की। लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही पहले स्थगित हुई और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी।लोकसभा में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने संशोधन विधेयक को मोदी सरकार की विफलताओं का प्रतीक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में पेपर लीक के मामले सामने आने पर तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इनकार किया था और इस बार भी सरकार का रवैया जिम्मेदारी से बचने वाला रहा। गोगोई ने यह भी सवाल उठाया कि छात्रों के प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया और इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा। उन्होंने संसद परिसर में भाजपा सांसदों द्वारा धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पर भी तीखी टिप्पणी की।भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि पेपर लीक की समस्या को केवल 2014 के बाद की घटना बताना पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पेपर लीक को "घोर अपराध" बता चुके हैं और सरकार की नीति दोषियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। उनके अनुसार इसी सोच के तहत कानून को और सख्त बनाने के लिए यह संशोधन लाया गया है।समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी ने प्रधानमंत्री को बचाने के लिए शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया है। उन्होंने जंतर-मंतर पर छात्रों के आंदोलन का उल्लेख करते हुए कहा कि "सरकार झुकती है, सिर्फ झुकाने वाला चाहिए।"तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि सरकार परीक्षाओं और छात्रों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है और नया कानून उसकी वर्षों की नाकामी को नहीं छिपा सकता। वहीं, द्रमुक सांसद दयानिधि मारन ने NEET परीक्षा की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए इसे समाप्त करने की मांग की।कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले एक दशक में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं हुईं, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए।

PoK के तथाकथित चुनावों को भारत ने किया खारिज

भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओके) में कराए जा रहे तथाकथित विधानसभा चुनावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें पाकिस्तान की ओर से अपने अवैध कब्जे को वैध ठहराने की एक "दिखावटी कवायद" करार दिया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पाकिस्तान ऐसे चुनावों के जरिए जमीनी हकीकत नहीं बदल सकता और न ही भारत की संप्रभुता पर कोई असर डाल सकता है।मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले क्षेत्र भी शामिल हैं, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पीओके में कराए जा रहे तथाकथित चुनाव केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे को वैध दिखाने और वहां जारी मानवाधिकार उल्लंघनों से अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान हटाने की कोशिश हैं।विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले लगभग दो महीनों से पीओके में चल रहे जनआंदोलन इस बात का प्रमाण हैं कि वहां के लोग पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों, प्रशासनिक दमन और बुनियादी अधिकारों के अभाव से असंतुष्ट हैं। भारत का कहना है कि इन परिस्थितियों में चुनाव कराना लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास है।

5 अगस्त से पहले फिर गरमाई जम्मू-कश्मीर की सियासत

अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर PDP का बड़ा ऐलान

5 अगस्त की तारीख नजदीक आते ही जम्मू-कश्मीर की राजनीति में एक बार फिर अनुच्छेद 370 का मुद्दा सुर्खियों में आ गया है। वर्ष 2019 में इसी दिन केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए को हटाकर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था। इसके साथ ही तत्कालीन राज्य का पुनर्गठन करते हुए लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जबकि जम्मू-कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तब से यह मुद्दा प्रदेश की राजनीति के केंद्र में बना हुआ है और विभिन्न राजनीतिक दल समय-समय पर इसकी बहाली की मांग उठाते रहे हैं।हालांकि, मौजूदा समय में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मुख्य फोकस जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा वापस दिलाने पर रखा है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने दिल्ली में प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की थी। इस प्रदर्शन में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) शामिल नहीं हुई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी दल पर सवाल भी उठाए थे।अब पीडीपी ने अपनी अलग रणनीति अपनाते हुए 5 अगस्त को पूरे जम्मू-कश्मीर में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी पार्टी अनुच्छेद 370 और 35ए की बहाली के साथ-साथ कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान की मांग को लेकर प्रदर्शन करेगी। यह घोषणा उन्होंने पीडीपी के 27वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की।महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता अपने-अपने जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सामने रखना है और जनता की भावनाओं को आवाज देना है।इस दौरान महबूबा मुफ्ती ने हाल ही में दिल्ली के जंतर-मंतर पर दिए गए अपने बयान को लेकर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि यदि कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा को लेकर की गई उनकी टिप्पणी से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं, तो

वह इसके लिए माफी मांगती हैं। गौरतलब है कि 23 जुलाई को महबूबा मुफ्ती ने जंतर-मंतर पहुंचकर परीक्षा में कथित अनियमितताओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समर्थन दिया था। उस दौरान उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा था कि कश्मीर की परिस्थितियां अलग हैं, क्योंकि वहां सुरक्षा बल आतंकवाद और उग्रवाद जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

29 जुलाई को मनाया जाएगा गुरु पूर्णिमा का पर्व

आषाढ़ मास की पूर्णिमा 29 जुलाई को है। इस तिथि पर गुरु पूजा का महापर्व गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। आम इंसान ही नहीं, भगवान ने भी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेदव्यास की जन्म तिथि है। वेदव्यास ने वेदों का संपादन किया। 18 मुख्य पुराणों के साथ ही महाभारत, श्रीमद् भागवत कथा जैसे ग्रंथों की रचना की थी। श्रीराम ने ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र से ज्ञान प्राप्त किया, श्रीकृष्ण के गुरु सांदीपनि थे। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि वैदिक पंचांग के अनुसार, गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई को शाम 6:18 मिनट से शुरू होकर 29 जुलाई को रात 8:05 मिनट तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जाएगा। हनुमान जी ने सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए थे। इसीलिए गुरु का स्थान सबसे ऊंचा माना गया है। गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरु की पूजा करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई उपहार दें और उनकी शिक्षाओं पर चलने का संकल्प लें। तभी जीवन में सुख-शांति के साथ ही सफलता भी मिल सकती है। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि भारत में इस दिन को बहुत श्रद्धा- भाव से मनाया जाता है। धार्मिक शास्त्रों में भी गुरु के महत्व को बताया गया है। गुरु को भगवान से भी श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि गुरु ही भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताते हैं।

पेपर लीक बिल पर प्रियंका गांधी का सरकार पर तीखा हमला

'युवाओं से डरती है सरकार, जवाब दें पीएम और गृह मंत्री'

लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेपर लीक की घटनाओं, शिक्षा व्यवस्था, छात्रों के विरोध-प्रदर्शनों पर हुई पुलिस कार्रवाई और नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति को लेकर सरकार की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए।बहस के दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि एक ओर सरकार जश्न मनाने में व्यस्त थी, वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र का एक परिवार कथित पेपर लीक प्रकरण के बाद अपनी बेटी को खोने के दुख से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सरकार को छात्रों के प्रति अधिक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। नए शिक्षा मंत्री की नियुक्ति का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इससे देश की छात्राओं के बीच न्याय, जवाबदेही और सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर गलत संदेश गया है।प्रियंका गांधी ने दावा किया कि सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों को लगातार कमजोर किया है, जहां से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। उनके अनुसार परीक्षा प्रणाली भी गंभीर संकट में है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में 152 बार पेपर लीक की घटनाएं सामने आईं, जिससे करोड़ों छात्र प्रभावित हुए, लेकिन किसी बड़े आरोपी या कथित पेपर लीक माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया गया है और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के केंद्रीकृत ढांचे ने समस्याओं को और बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुल केंद्रीय बजट में शिक्षा पर होने वाला व्यय अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ा है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया सोशल मीडिया बातचीत का जिक्र करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि केवल कैमरे का एंगल बदलने से वास्तविकता नहीं बदलती। उनका कहना था कि युवाओं की समस्याओं को समझने के लिए सरकार को अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा।उन्होंने संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सीधे जवाब मांगते हुए कहा कि छात्र आंदोलनों के दौरान हुई कथित पुलिस कार्रवाई पर देश को स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए। प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कथित तौर पर आंसू गैस, लाठीचार्ज, वाटर कैनन और पेलेट गन जैसे बल प्रयोग के आदेश किसने दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जानना चाहती है कि इन फैसलों की जिम्मेदारी किसकी है और सरकार इस पर सदन में जवाब दे।

इजराइल के विपक्षी नेता का बड़ा बयान, भारत में छिड़ी नई राजनीतिक बहस

इजराइल की राजनीति में एक बार फिर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल रही है। हालांकि इस बार विवाद घरेलू राजनीति नहीं, बल्कि अमेरिका की मध्यस्थता में प्रस्तावित इजराइल-सऊदी अरब समझौते को लेकर है। इस मुद्दे पर

विपक्ष के नेता यैर लैपिड ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर और अधिक सख्त रुख अपनाने की मांग की है।यैर लैपिड ने हाल ही में दिए अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को प्रस्तावित समझौते के दौरान इजराइल के सुरक्षा हितों पर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार, यदि अमेरिका की मध्यस्थता में सऊदी अरब और इजराइल के बीच संबंध सामान्य बनाने की दिशा में समझौता होता है, तो उसमें इजराइल की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।लैपिड ने कहा कि यदि समझौते के तहत सऊदी अरब औपचारिक रूप से इजराइल को मान्यता देता है और बदले में अमेरिका उसे सुरक्षा गारंटी तथा नागरिक परमाणु कार्यक्रम में सहयोग देता है, तो यह स्वीकार्य हो सकता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया कि सऊदी अरब को अपने स्तर पर यूरेनियम संवर्धन (यूरेनियम एनरिचमेंट) की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।विपक्षी नेता का तर्क है कि भविष्य में यदि यूरेनियम संवर्धन की क्षमता का दुरुपयोग हुआ, तो इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है और इजराइल के लिए नए खतरे पैदा हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस मुद्दे पर स्पष्ट और कठोर रुख अपनाना चाहिए तथा किसी भी ऐसी व्यवस्था से बचना चाहिए जो भविष्य में सुरक्षा जोखिम बन सके।लैपिड के इस बयान ने इजराइल में यह संदेश देने की कोशिश की है कि राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों पर विपक्ष सरकार की आलोचना तो करता है, लेकिन साथ ही सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर अपनी स्पष्ट नीति भी सामने रखता है। उनके बयान की चर्चा अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ-साथ भारत में भी हो रही है, जहां इसे विपक्ष की भूमिका को लेकर अलग-अलग नजरिए से देखा जा रहा है।

रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर कथित गोलीबारी 'अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च' के 14 समर्थकों की मौत का दावा

जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज़ असलम ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का काफिला चिनार चौक पहुँच गया था और रावलकोट में मकबूल भट्ट शहीद चौक पर रात भर रुकने से पहले D-चौक की ओर बढ़ रहा था। असलम ने कहा आज पाकिस्तान की सेना ने हमारे बेगुनाह युवाओं पर गोलीबारी की।

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च से जुड़े चश्मदीदों का दावा है कि सोमवार शाम रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कथित गोलीबारी में कम से कम 14 लोगों की मौत हो गई और लगभग दो दर्जन अन्य घायल हो गए। जारी किए गए एक वीडियो में, जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी (JAAC) के मुख्य सदस्य इम्तियाज़ असलम ने बताया कि विरोध प्रदर्शन का काफिला चिनार चौक पहुँच गया था और रावलकोट में मकबूल भट्ट शहीद चौक पर रात भर रुकने से पहले D - चौक की ओर बढ़ रहा था। असलम ने कहा आज पाकिस्तान की सेना ने हमारे बेगुनाह युवाओं पर गोलीबारी की। इसके नतीजतन, हमारे 14 युवा शहीद हो गए हैं। इनमें आंदोलन के संस्थापक उमर नज़ीर कश्मीरी के छोटे भाई उस्मान नज़ीर भी शामिल हैं। अन्य मृतकों में ख़ैगाला, कोटली शहर, टट्टापानी, बंजा-बासपुर, छोटा गाला और हवेली का एक-एक साथी शामिल है। कुल मिलाकर 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें हमारे दो बलूच साथी भी शामिल हैं। लगभग दो दर्जन अन्य लोग घायल हैं। उन्होंने विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने की अपील की और आरोप लगाया कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार कर रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से अपील करता हूं कि वे इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाएं। राज्य घबराहट की स्थिति में है और नरसंहार पर उतर आया है। उन्होंने कहा कि कृपया पाकिस्तानी दूतावासों और संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों के सामने विरोध प्रदर्शन करें। 'लॉन्ग मार्च' में शामिल लोगों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए रैलियां आयोजित करें। असलम ने मीरपुर और मुजफ्फराबाद डिवीजनों के लोगों से भी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में प्रदर्शन करने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी गई हैं, जिससे बातचीत करना मुश्किल हो गया है। ट्रांसपोर्ट की दिक्कतों की वजह से, हम अगले कुछ दिनों तक पैदल मार्च करेंगे। खुदा ने चाहा तो तीन-चार दिनों में हम शहीदों और ताकत के शहर, मुज़फ़्फ़राबाद पहुँच जाएँगे। उन्होंने आगे कहा कि आज रात 'अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च' अपना पहला पड़ाव मकबूल भट्ट शहीद चौक पर करेगा। एक और चश्मदीद ने बताया कि प्रदर्शनकारी सफ़ेद झंडे लेकर रावलकोट के चांदनी चौक पहुँचे और ज़ोर देकर कहा कि यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। हमारे युवा अल्लाहु अकबर के नारे लगाते हुए रावलकोट के चांदनी चौक पहुँच गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह! अल्लाह की मेहरबानी और रहमत से हम यहाँ पहुँच गए हैं। कई लोग शहीद हो चुके हैं, और इन निर्दयी लोगों ने हमारा बहुत खून बहाया है। फिर भी, मैं मंच से की जा रही उन घोषणाओं को सलाम करता हूँ जिनमें सेना से पीछे हटने का अनुरोध किया जा रहा है। हम शांतिप्रिय लोग हैं, सफेद झंडे लिए हुए हैं। कृपया पीछे हटें; हमारा आपसे कोई झगड़ा नहीं है।

अमेरिका और ईरान के बीच टकराव लाल सागर तनाव के एक नए मोर्चे के रूप में उभरा

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

सऊदी अरब समर्थित और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त यमन की सरकार ने कहा है कि हूती विद्रोही बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य में शिपिंग में बाधा डालकर ईरान की होर्मुज वाली रणनीति अपना रहा है। हाल के दिनों में हूतियों ने लाल सागर में जहाजों को निशाना बनाया है। हूती समूह की यमन के उत्तरी-पश्चिमी क्षेत्र के बड़े इलाके पर कब्जा है, जिसमें राजधानी सना भी शामिल है। यह इलाका लाल सागर और अदन की खाड़ी के पास पड़ता है। इस रास्ते से होकर दुनिया का सबसे अहम शिपिंग मार्ग गुजरता है। यमन की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार की विदेश मंत्री अफराह अल-जोबा ने कहा कि ईरान समर्थित यह समूह दुनिया के सबसे प्रमुख शिपिंग मार्गों में से एक पर प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है। अल-जोबा ने सोमवार को रियाद में पत्रकारों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा, "हूती विद्रोही ईरान के मॉडल की नकल करना चाहते हैं। इससे दो मुख्य जलडमरूमध्य बंद हो जाएंगा, जो फारस की खाड़ी और लाल सागर के प्रवेश द्वार हैं।" अमेरिका और ईरान के बीच टकराव के बीच लाल सागर तनाव के एक नए मोर्चे के रूप में उभरा है। हूती समूह ने पिछले सोमवार को लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की। इसने सऊदी तेल टैंकरों को निशाना बनाते हुए हमले किए। सऊदी अरब ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हूती सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वहीं हूतियों ने मिसाइल और ड्रोन के जरिए सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई की। लाल सागर एक अहम व्यापारिक जलमार्ग है, जो हिंद महासागर से आने वाले जहाजों को भूमध्य और अटलांटिक से जोड़ता है।

करीब 85 फीसदी पौधों का सत्यापन ही नहीं हुआ

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

राजस्थान में पिछले साल सरकारी रिकॉर्ड में पौधारोपण का आंकड़ा साढ़े ग्यारह करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन करीब 85 फीसदी पौधों का सत्यापन ही नहीं हुआ। राजस्थान में वर्ष 2025-26 के दौरान 72 विभागों ने 11.57 करोड़ पौधे लगाने और उनकी जियो टैगिंग का दावा किया है, लेकिन इनमें से केवल 1.69 करोड़ यानी करीब 14.6% पौधों का ही सत्यापन किया गया। सत्यापित पौधों में से 1.36 करोड़ पौधे जीवित पाए गए, जिससे सत्यापित पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत 80.83 फीसदी रहा। यह जानकारी सोमवार को लोकसभा में सीकर सांसद अमराराम के प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह की ओर से पेश आंकड़ों में सामने आई। आंकड़े बताते हैं कि पौधारोपण और उसके वास्तविक सत्यापन के बीच भारी अंतर है। कई विभागों ने लाखों पौधे लगाने का दावा किया, लेकिन उसका बहुत कम हिस्सा ही जियो टैगिंग के जरिए सत्यापित हो सका। लोकसभा में सरकार ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान वन विभाग ने पौधारोपण और रखरखाव पर 127.78 करोड़ रुपये खर्च किए। सबसे अधिक 4.03 करोड़ पौधे शिक्षा विभाग ने लगाए, लेकिन इनमें से केवल 28.63 लाख पौधों का सत्यापन हुआ। यानी कुल पौधारोपण का लगभग 7 फीसदी ही जांच के दायरे में आया। सत्यापित पौधों में 75.52 फीसदी जीवित पाए गए। वन विभाग ने 2.03 करोड़ पौधे लगाए, लेकिन 95.42 लाख पौधों का ही सत्यापन कराया। सत्यापित पौधों में 87.58 फीसदी जीवित मिले। राजस्थान में वर्ष 2025-26 के दौरान 72 विभागों ने 11.57 करोड़ पौधे लगाने और उनकी जियो टैगिंग का दावा किया है, लेकिन इनमें से केवल 1.69 करोड़ यानी करीब 14.6% पौधों का ही सत्यापन किया गया। सत्यापित पौधों में से 1.36 करोड़ पौधे जीवित पाए गए, जिससे सत्यापित पौधों का जीवित रहने का प्रतिशत 80.83 फीसदी रहा।

जापान के कुमामोटो में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि मंगलवार देर दोपहर जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू पर कुमामोटो में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। JMA ने बताया कि भूकंप समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर (6 मील) की गहराई पर आया। शाम 4:29 बजे आए भूकंप के बाद तुरंत किसी नुकसान या चोट की खबर नहीं मिली। यह भूकंप कुमामोटो के पश्चिमी इलाके में आया, जो टोक्यो से लगभग 900 किलोमीटर (540 मील) दक्षिण-पश्चिम में है। अमेरिकी पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने कहा कि स्थानीय तटों से आगे सुनामी का कोई खतरा नहीं है।जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने बताया कि मंगलवार देर दोपहर जापान के दक्षिणी मुख्य द्वीप क्यूशू पर कुमामोटो में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया और सुनामी की चेतावनी जारी की गई। JMA ने बताया कि भूकंप समुद्र की सतह से 10 किलोमीटर (6 मील) की गहराई पर आया। शाम 4:29 बजे आए भूकंप के बाद तुरंत किसी नुकसान या चोट की खबर नहीं मिली। यह भूकंप कुमामोटो के पश्चिमी इलाके में आया, जो टोक्यो से लगभग 900 किलोमीटर (540 मील) दक्षिण-पश्चिम में है। अमेरिकी पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ने कहा कि स्थानीय तटों से आगे सुनामी का कोई खतरा नहीं है।बता दें कि इससे पहले पिछले सप्ताह मैक्सिको में भी 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मैक्सिको को दक्षिणी राज्य चियापास के तट पर भूकंप के जबरदस्त झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद मैक्सिको में भी सुनामी की चेतावनीजारी की गई थी। भूकंप के झटके मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों तक महसूस किए गए। वहीं भूकंप से अल साल्वाडोर और ग्वाटेमाला जैसे पड़ोसी देश भी हिल गए।

तीन महिलाओं पर अचानक चाकू से हमला आरोपी ने दावा किया कि उसे अल्लाह ने ऐसा करने का आदेश दिया

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

पेरिस में हाल ही में हुए एक हमले ने पूरे फ्रांस को हिला दिया है। यह घटना पेरिस के पोर्ते दे क्लिशी इलाके के पास हुई थी। इस दौरान एक व्यक्ति ने तीन महिलाओं पर अचानक चाकू से हमला कर दिया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। इस दौरान हिम्मत दिखाते हुए मौके पर मौजूद लोगों ने और एक ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मी ने आरोपी को पकड़ लिया था जिसके चलते कोई बड़ा हादसा होने से पहले टल गया। खबरों के अनुसार आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान यह दावा किया कि उसे यह अपराध करने का आदेश अल्लाह ने दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज के बयान के अनुसार, आरोपी दो बड़े किचन चाकू लेकर सड़क पर पहुंचा और 19, 24 और 36 साल की तीन महिलाओं पर हमला कर दिया। हमले में घायल महिलाओं की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घायलों में एक महिला

गर्भवती भी है। तीन में से दो महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए है। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले स्नैपचैट पर इसका वीडियो सामने आया था जिसके बाद समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी इसकी पुष्टि की। वीडियो में लंबे काले बालों वाला एक व्यक्ति क्रीम रंग का ट्रैकसूट पहने दिखाई देता है। उसके दोनों हाथों में बड़े चाकू हैं और वह एक महिला पर हमला करने की कोशिश करता नजर आता है। वीडियो से यह साफ नहीं हो पाया कि उस समय महिला घायल हुई या नहीं। इसके बाद की क्लिप में आरोपी सड़क पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और उसके पास दोनों चाकू पड़े हैं। इसी दौरान वह कहता सुनाई देता है, मुझे अल्लाह ने आदेश दिया था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी 26 वर्षीय मोहम्मद अली बुहदजार ने बताया कि जैसे ही उन्होंने आरोपी को एक महिला की पीठ में चाकू मारते देखा, उन्होंने आसपास मौजूद लोगों से उसे रोकने की अपील की। एक व्यक्ति ने आरोपी की तरफ सूटकेस फेंका, जिससे उसके हाथ से दोनों चाकू गिर गए।

संपादक की कलम से

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के रावलकोट में 'अवामी हुकूक लॉन्ग मार्च' के दौरान प्रदर्शनकारियों पर कथित गोलीबारी और उसमें 14 लोगों के मारे जाने के दावे ने एक बार फिर इस क्षेत्र में मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन यदि यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि नागरिक अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों की बड़ी परीक्षा होगी।किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह असहमति की आवाज़ को सुनने और उसका शांतिपूर्ण समाधान खोजने की क्षमता रखती है। यदि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों के खिलाफ बल प्रयोग किया जाता है, तो इससे सरकार और जनता के बीच विश्वास की खाई और गहरी हो जाती है। दूसरी ओर, यदि प्रदर्शन हिंसक हो जाएं या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनें, तो प्रशासन की जिम्मेदारी कानून के दायरे में रहकर स्थिति को नियंत्रित करने की होती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है।PoK लंबे समय से राजनीतिक असंतोष, आर्थिक चुनौतियों और प्रशासनिक शिकायतों का सामना करता रहा है। स्थानीय संगठनों का आरोप है कि उन्हें पर्याप्त राजनीतिक अधिकार, संसाधन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिलती। ऐसे में यदि लोगों की मांगों को संवाद के बजाय बल से दबाने की कोशिश की जाती है, तो असंतोष और अधिक बढ़ सकता है। इतिहास बताता है कि किसी भी क्षेत्र में स्थायी शांति केवल सुरक्षा उपायों से नहीं, बल्कि न्याय, संवाद और जनविश्वास से स्थापित होती है।इस पूरे घटनाक्रम में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। संचार सेवाओं पर रोक अक्सर अफवाहों को रोकने के उद्देश्य से लगाई जाती है, लेकिन इससे सही जानकारी का प्रवाह भी बाधित होता है और घटनाओं की स्वतंत्र पुष्टि कठिन हो जाती है। ऐसे हालात में भ्रामक सूचनाएं और दावे तेजी से फैलते हैं, जिससे तनाव और बढ़ सकता है।अंतरराष्ट्रीय समुदाय और मानवाधिकार संगठनों की भूमिका भी ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि कहीं मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं, तो उनकी निष्पक्ष जांच और तथ्यों का सत्यापन आवश्यक है। इससे न केवल पीड़ितों को न्याय मिलने की संभावना बढ़ती है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में भी मदद मिलती है। आखिरकार, किसी भी सरकार की वास्तविक ताकत विरोध की आवाज़ को दबाने में नहीं, बल्कि उसे सुनने और लोकतांत्रिक तरीके से उसका समाधान निकालने में होती है। PoK की ताजा घटनाएं इसी मूल प्रश्न को सामने लाती हैं कि क्या बल प्रयोग से असंतोष खत्म किया जा सकता है, या फिर स्थायी समाधान केवल संवाद, पारदर्शिता और न्याय के रास्ते से ही संभव है।

संसद में NDA की 'मंगल मिलन' रणनीति पहली बार NCPI सांसद हुए शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखा जाये तो आज की मंगल मिलन बैठक में एनसीपीआई सांसदों की पहली मौजूदगी ने यह संकेत भी दे दिया कि एनडीए संसद के भीतर अपना कुनबा लगातार बढ़ाने में जुटा है।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

संसद के मानसून सत्र में जहां विपक्ष छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेरते हुए दोनों सदनों को नहीं चलने दे रहा है वहीं सत्ता पक्ष ने भी अपने राजनीतिक मोहरे एक-एक कर सजा दिए हैं। संसद परिसर में आज हुई एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक 'मंगल मिलन' बैठक मात्र फ्लोर मैनेजमेंट तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने यह संदेश भी दे दिया कि संसद के भीतर संख्या, समन्वय और रणनीति, तीनों मोर्चों पर एनडीए अब और अधिक आक्रामक अंदाज में उतरने वाला है। खास बात यह रही कि तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर बनी नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया (NCPI) के सांसद पहली बार एनडीए की औपचारिक रणनीतिक बैठक का हिस्सा बने, जिससे विपक्षी खेमे में हलचल तेज हो गई।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि संसद सत्र के दौरान प्रत्येक मंगलवार को होने वाली इन बैठकों का मकसद संसद के भीतर सहयोगी दलों के बीच तालमेल मजबूत करना, विधेयकों पर साझा रणनीति बनाना और विपक्ष के हमलों का एकजुट होकर जवाब देना होता है। इस बार बैठक का सबसे बड़ा एजेंडा था पब्लिक एग्जामिनेशंस (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक-2026। सोमवार को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक पर विपक्ष के भारी हंगामे के बीच चर्चा आगे बढ़ाने के लिए एनडीए ने पूरी तैयारी कर ली है। सरकार का दावा है कि यह कानून पेपर लीक और संगठित परीक्षा घोटालों पर अब तक का सबसे कठोर प्रहार साबित होगा। सरकार का कहना है कि अब केवल 'नकलची' नहीं, बल्कि पूरे 'पेपर लीक उद्योग' पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। उधर, विपक्ष इस पूरे मुद्दे को केवल कानून का सवाल नहीं, बल्कि सरकार की जवाबदेही का विषय बना रहा है। 20 जुलाई के 'संसद चलो' छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है। देखा जाये तो आज की मंगल मिलन बैठक में एनसीपीआई सांसदों की पहली मौजूदगी ने यह संकेत भी दे दिया कि एनडीए संसद के भीतर अपना कुनबा लगातार बढ़ाने में जुटा है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष को साफ संदेश दे दिया है कि उसकी रणनीति बचाव की नहीं, बल्कि पलटवार की है। उधर, एनसीपीआई की सांसद सायोनी घोष ने कहा, "मैंने राजग की बैठक में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में यह एक अत्यंत ज्ञानवर्धक बैठक थी। आज हमने मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर चर्चा की। यह काफी सकारात्मक चर्चा रही।" उन्होंने लोकसभा में आज चर्चा के लिए पेश किये जाने वाले 'लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक 2026' का संदर्भ देते हुए कहा कि प्रश्नपत्र लीक रोधी इस विधेयक का सभी को समर्थन करना चाहिए। एक अन्य सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने बताया कि यह पहला मौका था जब एनसीपीआई के 20 सांसदों को राजग की 'मंगल मिलन' बैठक में आमंत्रित किया गया।

प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कानूनी मदद देगी शिवसेना (UBT): आदित्य ठाकरे

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

शिवसेना (UBT) के विधायक आदित्य ठाकरे ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्र और विभिन्न राज्यों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकारें परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को निशाना बना रही हैं। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में विरोध-प्रदर्शन में शामिल छात्रों पर अब भी पुलिस कार्रवाई जारी है, जबकि सरकार की ओर से उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का आश्वासन दिया गया था।पत्रकारों से बातचीत के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि पिछले दस दिनों से देश के कई शहरों में छात्र परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता की मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। उनका कहना था कि यह आंदोलन युवाओं के बढ़ते असंतोष का प्रतीक है और सरकार को छात्रों की आवाज़ सुननी चाहिए, न कि उन्हें कानूनी मामलों में उलझाना चाहिए।ठाकरे ने बताया कि शिवसेना (UBT) ने ऐसे छात्रों को हरसंभव कानूनी सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि यदि किसी छात्र को पुलिस की ओर से नोटिस मिलता है या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाता है, तो वह पार्टी से संपर्क करे। पार्टी से जुड़े कई अधिवक्ता इन मामलों की पैरवी निःशुल्क करेंगे। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर तत्काल वापस लेने की मांग भी की।प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए आदित्य ठाकरे ने आरोप लगाया कि छात्रों के खिलाफ आवश्यकता से अधिक बल का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने अत्यधिक लाठीचार्ज या अन्य कठोर कार्रवाई की है, उनकी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार का रवैया युवाओं के हितों के विपरीत है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ कठोर व्यवहार किया गया।इसके साथ ही ठाकरे ने महाराष्ट्र में आयोजित MH-CET प्रवेश परीक्षा की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए। उन्होंने राज्य सरकार से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और छात्रों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उनका कहना था कि यदि परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता की आशंका है, तो सरकार को उस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि छात्रों का विश्वास शिक्षा व्यवस्था पर बना रहे।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य बोले- युवाओं को भड़काने की रची गई साज़िश

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े पर राजस्थान में जयपुर के हवामहल विधानसभा क्षेत्र से BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने ऐतिहासिक विकास देखा है। देश-विदेश में भारत का मान-सम्मान बढ़ा है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए खास योजनाएं लागू की गई हैं, फिर चाहे खेल हो या फिर एंटरप्रेन्योर या व्यापारी हों, सभी के लिए कुछ ना कुछ किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे युवाओं को भड़काने की साज़िश रची। BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि हम पेपर लीक के पूरी तरह से खिलाफ हैं। कोई भी जान-बूझकर ऐसी हरकत नहीं करता, लेकिन जिन्होंने ऐसा किया है, वे सज़ा के हकदार हैं और उन्हें सज़ा मिलेगी। BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सवाल किया कि क्या उस युवा आंदोलन में ऐसे लोग भी शामिल थे जो देश में अराजकता फैलाना चाहते थे? क्या इसमें देश-विरोधी ताकतों का हाथ था? बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है और जवाबदेही व नैतिक आचरण की एक बड़ी मिसाल पेश की है। हालांकि, मनीष सिसोदिया ने एक बार कहा था कि अगर उनके कार्यकाल में पेपर लीक हुआ तो वे इस्तीफ़ा दे देंगे। फिर भी, मौजूदा सरकार के कार्यकाल में पंजाब में छह या सात बार पेपर लीक हो चुके हैं। बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि सभी विपक्षी दलों ने मिलकर एक खास तरह का माहौल बनाने की साज़िश रची। अगर आपने 2014 से मोदी को सुना, समझा और देखा है, और उनके काम करने के तरीके को समझा है, तो आपको एहसास हुआ होगा कि उन्होंने हमेशा युवाओं को सबसे आगे रखा है। किसानों, युवाओं और महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी गई है, और ठोस कदमों के जरिए सबसे गरीब लोगों के कल्याण पर ध्यान दिया गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के बीते 36 दिन से जंतर-मंतर पर धरने के बीच 25 जुलाई दोपहर को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया था। शनिवार शाम करीब 8.15 बजे धर्मेंद्र प्रधान के मंत्रालय का चार्ज प्रह्लाद जोशी को दे दिया गया है।प्रह्लाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री भी हैं।

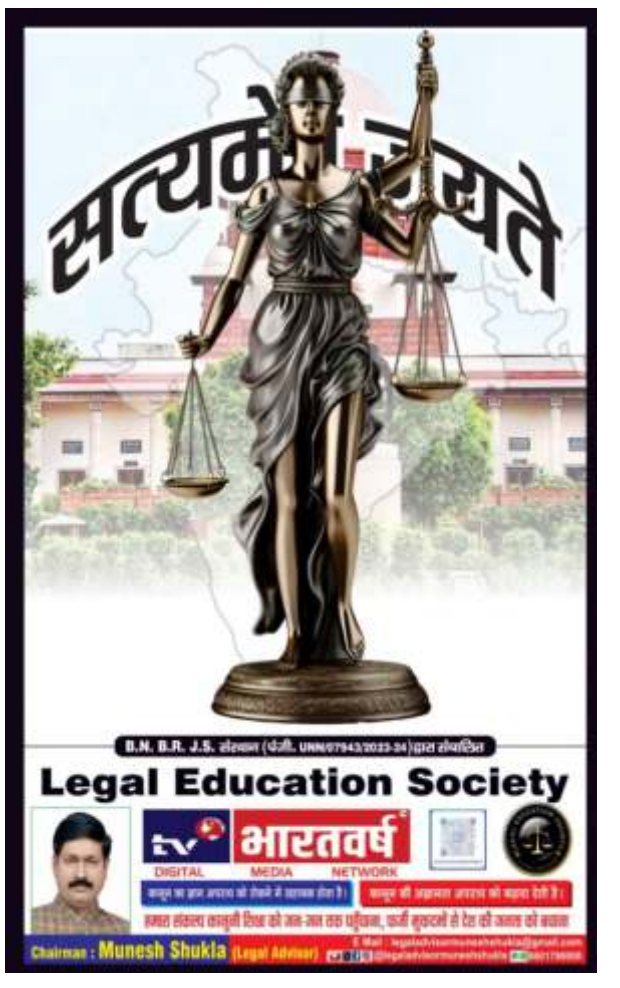

विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा SBI दे रहा ₹15 लाख तक की आशा स्कॉलरशिप

विदेश में पढ़ाई करने की राह में सबसे बड़ी बाधा डिग्री लेने पर होने वाला खर्च है। फीस के साथ-साथ रहने-खाने पर भी पैसा खर्च करना पड़ता है, जिस वजह से बहुत से स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने का प्लान ड्रॉप कर देते हैं। अच्छी बात ये है कि कई सारे संस्थान भारतीय स्टूडेंट्स के विदेश में पढ़ने के सपने को पूरा करने के लिए स्कॉलरशिप भी देते हैं। आज हम एक ऐसी ही स्कॉलरशिप के बारे में जानेंगे, जिसके लिए आप भी अप्लाई कर सकते हैं।

दरअसल, अगर आप विदेश के किसी टॉप संस्थान में पोस्टग्रेजुएट डिग्री या हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। देश का सबसे बड़ा बैंक- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अपने स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर SBI प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026-27 दे रहा है। इस स्कॉलरशिप का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स को वित्तीय सहायता देना है, ताकि पैसों की तंगी उनके विदेश में पढ़ने के सपनों के आड़े नहीं आए। SBI स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत विदेश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स को 15 लाख रुपये की भारी-भरकम आर्थिक मदद दी जाएगी। ये स्कॉलरशिप सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है, जिस वजह से कॉम्पिटिशन सिर्फ भारतीयों के बीच ही रहेगा। स्कॉलरशिप सिर्फ पोस्टग्रेजुएट या मास्टर डिग्री के लिए दी जा रही है। इसके जरिए बैचलर्स की पढ़ाई नहीं की जा सकती है। आइए स्कॉलरशिप से जुड़ी जरूरी डिटेल्स भी जान लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऊपर बताई गईं शर्तों का पालन करते हैं, तो फिर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा करने से पहले आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखने हैं। आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए।

इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे स्टूडेंट्स को मालूम होना चाहिए कि इसमें आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों के लिए सीटें रिजर्व भी हैं। एप्लिकेशन लिंक पर क्लिक कर स्कॉलरशिप के लिए न सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि हर कैटेगरी के लिए तय की गई सीटों की संख्या के बारे में भी जान सकते है। तय समय सीमा के भीतर अपनी कागजी कार्रवाई पूरी करें और इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करें।

अमेरिका में कई ऐसे वीजा हैं, जो सीधे ग्रीन कार्ड दिलाते हैं।

अमेरिका में टैलेंटेड भारतीयों के लिए परमानेंट रेजिडेंसी (PR) हासिल करना ज्यादा लंबा रास्ता नहीं रहा है, क्योंकि यहां पर कई सारे ऐसे वीजा प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जिनके जरिए देश में बसना आसान रहा है। EB-1 वीजा (एंप्लॉयमेंट बेस्ड फर्स्ट कैटेगरी) अमेरिकी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए टॉप-टियर कैटेगरी है। इस वीजा के दायरे में आने वाले लोगों को सबसे जल्दी PR मिलता है और सिर्फ उन्हीं लोगों को प्राथमिकता मिलती है, जो टैलेंटेड हैं। EB-1 वीजा उन लोगों के लिए है, जिनके पास असाधारण योग्यता है। प्रोफेसर या रिसर्चर्स और मल्टीनेशनल कंपनियों के मैनेजर या एग्जिक्यूटिव को भी EB-1 वीजा दिया जाता है। एक समय EB-1 ग्रीन कार्ड पाने का सबसे तेज तरीका हुआ करता था, क्योंकि इसमें बैकलॉग बहुत कम या बिल्कुल नहीं था। ज्यादातर लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं था, क्योंकि वे इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। बहुत कम लोग ही इस वीजा के लिए क्वालिफाई कर पाते थे। हालांकि, अगस्त के लिए जारी हुए वीजा बुलेटिन में अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चेतावनी देते हुए बताया कि 2026 वित्त वर्ष, जो सितंबर में खत्म हो रहा है। उसमें भारतीयों के लिए EB-1 वीजा उपलब्ध नहीं होने की संभावना है। इसका मतलब है कि अगर आप अमेरिका में प्रोफेसर, रिसर्चर, मैनेजर या एग्जिक्यूटिव जैसी पॉजिशन पर काम कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए ग्रीन कार्ड का इंतजार लंबा हो जाएगा।विदेश मंत्रालय ने कहा, 'EB-1 वीजा कैटेगरी में भारत से जुड़े लोगों की ज्यादा मांग और वीजा के इस्तेमाल की वजह से, आने वाले हफ्तों में इस कैटेगरी को बंद करना पड़ सकता है। ऐसा तभी होगा, अगर वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही EB-1 कैटेगरी में भारत की तय सीमा पूरी हो जाती है। इस स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और जरूरत के हिसाब से जरूरी बदलाव किए जाएंगे।'

श्रीकांत ने संजू सैमसन को भारत की T20I टीम में वापस लाने का समर्थन किया

शर्मिला धनकर ने जीता ऐतिहासिक स्वर्ण पदक

ग्लास्गो , 27 जुलाई दो वर्ष की उम्र में पोलियो का शिकार हुई और शादी के बाद लगातार अपमान के सदमे से उबरकर शर्मिला धनकर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली पैरा एथलीट बन गई जिन्होंनेमहिला शॉट पुट एफ57 स्पर्धा में पहला स्थान हासिल किया। चालीस वर्षीय शर्मिला ने 9.81 मीटर का सत्र का सर्वश्रेष्ठ थ्रो लगाकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पैरा एथलेटिक्स पदक के 20 साल के इंतजार को खत्म किया। इस स्पर्धा में एक और भारतीय खिलाड़ी शिल्पा शायला को विवाद के बाद कांस्य पदक प्रदान किया गया। शिल्पा ने 7.26 मीटर का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था। शुरुआत में नाइजीरिया की यूचेरिया इयियाजी कांस्य पदक की स्थिति में थीं, लेकिन भारतीय दल की आपत्ति और आधिकारिक समीक्षा के बाद उनके एकमात्र वैध प्रयास को फाउल करार दिया गया। इसके बाद चौथे स्थान पर रहीं शिल्पा शायला को कांस्य पदक मिल गया। नाइजीरिया की ओर से हालांकि इस फैसले के खिलाफ आपत्ति दर्ज किए जाने की संभावना है। पदक में बदलाव की घोषणा के बाद भावुक शिल्पा ने शर्मिला के साथ जश्न मनाया। इस तरह भारत ने इस स्पर्धा में दो पदक हासिल किए। एफ57 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए होता है जिनके निचले अंगों में अक्षमता, अंगों की कमी या मांसपेशियों की ताकत में कमी होती है। शर्मिला का यह पदक उनके बेहतरीन खेल ही नहीं बल्कि अप्रतिम साहस की भी कहानी बताता है। हरियाणा के छितरोली की रहने वाली शर्मिला दो वर्ष की थी जब पोलियो के कारण उनके बायें पैर में विकार आ गया था। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साझा किये गए परिचय के अनुसार शर्मिला का विवाह जल्दी हो गया था और उनके पति का बर्ताव बेहद खराब था। अपने परिवार के सहयोग से वह जीवन को फिर ढर्रे पर ला सकी। उन्होंने रेवाड़ी के व्यवसायी अजित सिंह से दोबारा विवाह किया और उनके दो बच्चे हैं।

श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की हुई वापसी

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने श्रीलंका के खिलाफ अगस्त में होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमिटी ने शुभमन गिल की कप्तानी में 15 सदस्यों की टीम चुनी है, जिसमें केएल राहुल उप-कप्तान बने रहेंगे। टीम के ऐलान की सबसे खास बात अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की वापसी है, जो इस दौरे के लिए टेस्ट टीम में लौट आए हैं। उम्मीद के मुताबिक, चोट की वजह से पहले टेस्ट से बाहर होने के बाद ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल नहीं किया गया है। उनके न होने से स्पिन-बॉलिंग के दूसरे विकल्पों के लिए रास्ते खुल गए हैं, क्योंकि भारत श्रीलंका में ऐसी परिस्थितियों के लिए तैयारी कर रहा है जिनसे धीमे गेंदबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। चयनकर्ताओं ने स्पिन विभाग को मजबूत बनाए रखा है और दो मैचों की इस सीरीज के लिए रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव और मानव सुथार जैसे विकल्प मौजूद हैं। जडेजा की वापसी से गेंदबाजी आक्रमण के मजबूत होने की उम्मीद है, क्योंकि कप्तान शुभमन गिल भारत को ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाने की दौड़ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज़ गेंदबाज़ जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज़ साई सुदर्शन, दोनों को ही टीम में शामिल किया गया है। हालाँकि, सीरीज़ में उनका खेलना उनकी फ़िटनेस पर निर्भर करेगा। मैचों के लिए उनकी उपलब्धता पर टीम मैनेजमेंट के फ़ाइनल फ़ैसले से पहले, इन दोनों खिलाड़ियों का फ़िटनेस टेस्ट होगा। इस बीच, मध्य प्रदेश के ऑफ़-स्पिन ऑल-राउंडर सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में बुलाया गया है। श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की टीम: शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जयसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन*, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवीन्द्र जड़ेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रित बुमराह*, मोहम्मद सिराज, प्रसीद कृष्ण, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन।

33 साल की उम्र में सारांश जैन को भारतीय टीम से आया बुलावा

8 जुलाई को श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। घरेलू क्रिकेट के जाने-माने नाम सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में जगह दी गई है। 33 साल के सारांश मध्यप्रदेश की तरफ से घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और टीम का बड़ा चेहरा हैं। अब वह श्रीलंका में अपना जलवा दिखाने के लिए तैयार हैं। सारांश जैन का जन्म 31 मार्च 1993 को इंदौर में हुआ था। बाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ से ऑफ-स्पिन गेंदबाजी करने वाले सारांश जैन ने 21 साल की उम्र में 2014 में मध्यप्रदेश के लिए प्रथम श्रेणी में डेब्यू किया था। सारांश ने मध्यप्रदेश के लिए 2017 में लिस्ट ए और टी20 में भी डेब्यू किया। डेब्यू के बाद से वह इस टीम के नियमित और प्रभावशाली खिलाड़ी रहे हैं।जैन एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से मध्यप्रदेश टीम को मजबूत संतुलन देते हैं। प्रथम श्रेणी में लगातार उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। मुंबई को हराकर 2021-2022

का रणजी ट्रॉफी खिताब जीतने वाली टीम के सदस्य रहे सारांश ने 2025-26 रणजी ट्रॉफी में मध्यप्रदेश के लिए 7 मैचों में 30 विकेट लिए। भारतीय टीम मैनेजमेंट टेस्ट फॉर्मेट में एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश में है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी में निपुण हो और टीम को खेल के दोनों विभागों में मजबूती दे सके। जैन टीम की इस जरूरत को पूरा करने के श्रेष्ठ विकल्प के रूप में उभरे हैं। उनके लंबे अनुभव ने भी टीम इंडिया में उनके चयन में अहम भूमिका निभाई है। देखना होगा कि श्रीलंका में भारतीय टीम के लिए डेब्यू करने का उनका लंबा इंतजार समाप्त होता है या नहीं।सांराश के घरेलू करियर पर गौर करें, तो 54 प्रथम श्रेणी मैचों की 85 पारियों में 2 शतक और 14 अर्धशतक लगाते हुए 2,223 रन बनाने के अलावा, वे 188 विकेट ले चुके हैं। वहीं, 47 लिस्ट ए मैचों की 35 पारियों में 553 रन और 38 विकेट, और 20 टी20 मैचों में उन्होंने 18 विकेट लिए हैं।

माचिस की डिब्बी से लगती है उपस्थिति

ठीचर ने हाजिरी का निकाला गजब तरीका

दिल्ली के एक स्कूल की टीचर ने अटेंडेंस लेने का ऐसा अनोखा तरीका निकाला है, जिसमें न रोल नंबर पुकारा जाता है और न ही बच्चे 'प्रेजेंट मैम' कहते हैं. माचिस की डिब्बियों से जुड़ा यह देसी आइडिया सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रहा है

स्कूल की यादों में ये याद हर किसी की जहन में रहती है. स्कूल की घंटी बजते ही क्लास में सबसे पहले अटेंडेंस शुरू होती है. टीचर एक-एक छात्र का नाम या रोल नंबर पुकारते हैं और बच्चे जवाब देते हैं-प्रेजेंट मैम. और हो गया ये हाजिरी का काम और ,स्कूल की शुरूआत.लेकिन कोई कहे अब इस तरीके का थोड़ा सा मोडिफाइड कर दें. यानी ये कोई प्रेजेंट मैम और अटेंडेस मैम नहीं हो. बस एक काम हो हो गई अटेंडेंस. दिल्ली के एक स्कूल की टीचर ने अटेंडेंस लेने का ऐसा अनोखा तरीका अपनाया है, जिसने सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. इस अनोखे आइडिया का वीडियो इंस्टाग्राम पेज @mind_map_master ने शेयर किया है. वीडियो में बच्चे क्लास में आते ही अपनी सीट पर नहीं बैठते. सबसे पहले वे दीवार पर लगे एक रंग-बिरंगे बोर्ड के पास जाते हैं. इस बोर्ड पर हर छात्र के नाम और फोटो वाली छोटी-छोटी माचिस की डिब्बियां लगी हुई हैं. हर डिब्बी के अंदर 'A' (Absent) और 'P' (Present) लिखा हुआ है. जैसे ही छात्र क्लास में पहुंचते हैं, वे अपनी डिब्बी को खिसकाकर 'P' पर कर देते हैं. यानी बच्चे खुद अपनी हाजिरी लगाते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में टीचर को किसी का नाम पुकारने की जरूरत नहीं पड़ती. वीडियो देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि यह सिर्फ अटेंडेंस लेने का तरीका नहीं है, बल्कि बच्चों में जिम्मेदारी और ईमानदारी की भावना विकसित करने का शानदार प्रयास है.

बिना तकनीक के भी हो सकता है इनोवेशन

ऐसे समय में जब स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसी तकनीकों पर जोर दिया जा रहा है, यह छोटा-सा आइडिया दिखाता है कि अच्छा इनोवेशन महंगे उपकरणों का मोहताज नहीं होता. कुछ खाली माचिस की डिब्बियां, कार्डबोर्ड, बच्चों की तस्वीरें और एक अलग सोच रखने वाला शिक्षक भी सीखने का अनुभव यादगार बना सकता है.

विदेश जाने के बाद क्यों नहीं लौटते कई भारतीय?

विदेश जाने वाले कई भारतीय शुरुआत में यही सोचते हैं कि कुछ साल नौकरी करेंगे, अच्छी कमाई करेंगे और फिर भारत लौट आएंगे. लेकिन समय के साथ कई लोगों का फैसला बदल जाता है. अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय ने अब बताया है कि आखिर ऐसा क्यों होता है. अमेरिका में रहने वाले गौरव मखलोगा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर अपने अनुभव साझा किए.

नौकरी छोड़ शुरू की चाय की दुकान, अब ₹1.8 लाख की सेल!

आज के समय में ज्यादातर लोग एक अच्छी नौकरी पाने का सपना देखते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नौकरी छोड़कर अपना कारोबार शुरू करने का फैसला करते हैं. ऐसा ही एक मामला इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. एक शख्स ने 38 हजार रुपये महीने की नौकरी छोड़कर चाय की दुकान खोली. दावा किया जा रहा है कि आज उसकी दुकान से हर महीने करीब 1.8 लाख रुपये की बिक्री हो रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शख्स पहले टेली परफॉर्मेंस कंपनी में काम करता था और हर महीने करीब 38 हजार रुपये कमाता था. हालांकि, नौकरी से संतुष्ट न होने की वजह से उसने मई महीने में नौकरी छोड़ने का

फैसला किया.

परिवार और दोस्तों ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन उसने अपनी मेहनत और बिजनेस आइडिया पर भरोसा किया. नौकरी छोड़ने के बाद उसने करीब 2 लाख रुपये का निवेश किया और एक ऑटो स्टैंड के पास चाय की दुकान खोल दी. दुकान में उसने दो तरह की चाय रखी.

सिफारिशों से नहीं मिलेगी फर्स्ट क्लास सीट

हवाई यात्रा करने वाले ज्यादातर लोगों का सपना होता है कि एक बार फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास में सफर करने का मौका मिले. कई लोग सोचते हैं कि एयर होस्टेस से रिक्वेस्ट कर देंगे, ज्यादा पैसे दे देंगे या फिर कोई खास बहाना बना देंगे तो उन्हें अपग्रेड मिल जाएगा. लेकिन 15 साल का अनुभव रखने वाली एक एयर होस्टेस ने बताया है कि असलियत इससे बिल्कुल अलग है.

न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट अटेंडेंट बारबरा बैसिलिएरी के मुताबिक, लोग अक्सर फर्स्ट क्लास में अपग्रेड पाने के लिए तरह-तरह की तरकीबें अपनाते हैं. कोई कहता है कि वह हनीमून पर जा रहा है, तो कोई केबिन क्रू को खुश करने की

कोशिश करता है. लेकिन सच यह है कि इन तरीकों का कोई फायदा नहीं होता.

बारबरा बताती हैं कि ज्यादातर एयरलाइंस में फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास का अपग्रेड बोर्डिंग शुरू होने से कई घंटे पहले ही तय कर दिया जाता है. जब तक यात्री फ्लाइट अटेंडेंट से अपग्रेड की बात करते हैं, तब तक फैसला हो चुका होता है. केबिन क्रू सिर्फ उसी लिस्ट के हिसाब से काम करता है, जो एयरलाइन पहले से तैयार करके देती है. उन्होंने बताया कि आमतौर पर एयरलाइन अपने लॉयल यानी ज्यादा उड़ान भरने वाले यात्रियों (फ्रीक्वेंट फ्लायर) को प्राथमिकता देती है. जिनका स्टेटस ज्यादा होता है, उनके अपग्रेड होने की संभावना भी अधिक रहती है.

'बंटवारा 1947' का दमदार ट्रेलर रिलीज

14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी बहुचर्चित फिल्म 'बंटवारा 1947' का आधिकारिक ट्रेलर जारी कर दिया गया है। राजकुमार संतोषी के निर्देशन में बनी यह ऐतिहासिक ड्रामा फिल्म 14 अगस्त 2026 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। लंबे समय से इस प्रोजेक्ट को लेकर बन रही उत्सुकता के बीच सामने आया यह ट्रेलर दर्शकों को भारत के विभाजन के दौर की त्रासदी और मानवीय संवेदनाओं से रूबरू कराता है।यह फिल्म 1947 में हुए देश के बंटवारे के दौरान उपजी परिस्थितियों और उसके बाद आम लोगों के जीवन पर पड़े प्रभाव को केंद्र में रखती है। कहानी एक ऐसे परिवार की त्रासदी को दर्शाती है, जो रातों-रात हुई हिंसा, डर और विस्थापन की वजह से बिखर जाता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि कैसे सदियों से साथ रहने वाले लोग राजनीतिक फैसलों और नफरत की आग में एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। हालांकि इस विनाशकारी पृष्ठभूमि के बीच भी फिल्म उम्मीद, मानवीय गरिमा और एक-दूसरे के प्रति हमदर्दी की लौ को जलाए रखने का संदेश देती है।फिल्म की मुख्य स्टारकास्ट में सनी देओल, शबाना आजमी और प्रीति जिंटा शामिल हैं। करीब तीन दशक बाद निर्देशक राजकुमार संतोषी और सनी देओल एक बार फिर किसी सिनेमाई प्रोजेक्ट के लिए साथ आए हैं। ट्रेलर में सनी देओल का किरदार अपने उसूलों और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष करता नजर आता है। वहीं दिग्गज अभिनेत्री शबाना आजमी एक ऐसी बुजुर्ग महिला का किरदार निभा रही हैं, जो विपदा के समय परिवार और समाज के लिए एक वैचारिक सहारा बनती हैं। प्रीति जिंटा एक संघर्षशील महिला के रूप में दिखती हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने परिवार को बिखरने से बचाने का प्रयास करती है। फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है और इसमें एक भी कट नहीं लगाया गया। फिल्म की सपोर्टिंग कास्ट में करण देओल, अली फजल और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आएंगे। 'बंटवारा 1947' का संगीत ऑस्कर विजेता संगीतकार एआर रहमान ने तैयार किया है, जबकि इसके गीत जावेद अख्तर द्वारा लिखे गए हैं। अपर्णा पुरोहित ने संयुक्त रूप से किया है। ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में विजुअल डिटेल्स और उस दौर के माहौल को बारीकी से पर्दे पर उतारने की कोशिश की गई है। 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही यह फिल्म केवल एक ऐतिहासिक घटना की याद नहीं दिलाती, बल्कि उस दौर में आम लोगों द्वारा झेले गए दर्द और उनके साहस की एक सिनेमाई प्रस्तुति है।

लोकसभा में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला बोले- 'एक प्रधान को हटाकर प्रधानमंत्री को बचा लिया'

लोकसभा में लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) संशोधन विधेयक-2026 पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने सरकार पर पेपर लीक रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि सरकार ने इसे परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और सख्त बनाने वाला कदम बताया।

लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय से इस अहंकार में थी कि वह कभी झुकती नहीं है, लेकिन देशभर के छात्रों और युवाओं के आंदोलन ने उसे झुकने के लिए मजबूर कर दिया। अखिलेश ने दावा किया कि युवाओं के संघर्ष का सबसे बड़ा परिणाम केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा रहा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकार ने "प्रधान" को हटाकर "प्रधानमंत्री" को बचाने का काम किया।अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे देश ने देखा कि मंत्री पद छोड़ने के बाद भी संसद के बाहर उनका जिस तरह स्वागत किया गया, उससे यह साफ हो गया कि भाजपा अपने नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें स्वागत से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इससे यह जरूर जाहिर होता है कि पार्टी के सांसदों ने राहत की सांस ली कि बड़ा राजनीतिक संकट टल गया।सपा प्रमुख ने कहा कि हाल के छात्र आंदोलन ने यह साबित कर दिया कि देश की नई पीढ़ी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि आंदोलन के दौरान लगे नारों ने यह संदेश दिया कि सरकार को भी जनता के दबाव में झुकना पड़ता है। उनके मुताबिक भाजपा जनता से किए गए वादे पूरे नहीं करती, बल्कि केवल जुमलेबाजी करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अब परीक्षा संशोधन विधेयक इसलिए लेकर आई है क्योंकि छात्रों के व्यापक आंदोलन ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया।अखिलेश यादव ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो सरकार अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी रोकने में सफल नहीं हुई, वह पेपर लीक जैसे संगठित अपराध पर कैसे प्रभावी नियंत्रण कर पाएगी। उन्होंने दावा किया कि अकेले उत्तर प्रदेश में 20 से अधिक प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं और जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन में सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश के छात्रों और युवाओं की थी।अपने संबोधन में उन्होंने किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया और कहा कि केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून भी तब वापस लिए, जब लंबे आंदोलन और चुनावी दबाव का सामना करना पड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल तब फैसले बदलती है, जब वह जनता के आक्रोश और राजनीतिक दबाव से घिर जाती है।भाषण के अंत में अखिलेश यादव ने आपातकाल का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने इमरजेंसी का दौर नहीं देखा, लेकिन दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुईं, उन्होंने उन्हें उस दौर की याद दिला दी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस और अन्य बल प्रयोग किया गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।

हाईकोर्ट ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले वकीलों की सूची तलब की

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने जिला कचहरी परिसर में हुई मारपीट की घटना को गंभीरता से लेते हुए आपराधिक रिकॉर्ड वाले वकीलों की सूची तलब की है। न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने यह आदेश कैसरबाग स्थित कचहरी में एक वादकारी और दिल्ली से आए उसके वकीलों के साथ हुई मारपीट के मामले में स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।कोर्ट ने संयुक्त आयुक्त (कानून-व्यवस्था) को अगली सुनवाई तक आपराधिक पृष्ठभूमि वाले वकीलों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। साथ ही, डीसीपी पश्चिम और संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) को 13 अगस्त को अगली सुनवाई के दौरान अब तक की कार्रवाई का विस्तृत ब्यौरा लेकर अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है।सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि मामले के मुख्य आरोपी सौरभ वर्मा ने आत्मसमर्पण कर जेल भेजे जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि अन्य नामजद आरोपियों, विशेषकर हर्षित दीक्षित, की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी। जवाब में डीसीपी पश्चिम ने अदालत को भरोसा दिलाया कि पुलिस लगातार दबिश दे रही है और शेष सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस को प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

लखनऊ के न्यू विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरकर पूर्व मंत्री नानक राम भुर्जी की मौत

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सबसे व्यस्त और सुरक्षित माना जाने वाला हजरतगंज इलाका मंगलवार दोपहर अचानक गोलियों या चीखों से नहीं, बल्कि एक भारी गिरावट की आवाज़ से सिहर उठा। दारुलशफा स्थित न्यू विधायक निवास परिसर की सातवीं मंजिल से गिरकर पूर्व राज्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नानक राम भुर्जी (68) की असामयिक और संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। जैसे ही 68 वर्षीय भाजपा नेता के ऊंचाई से गिरने की सूचना विधायक आवास के सुरक्षा प्रभारी को मिली, उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस चौकी और हजरतगंज कोतवाली को आगाह किया। आनन-फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची और लहूलुहान अवस्था में पड़े पूर्व मंत्री को तुरंत नजदीकी श्यामा प्रसाद मुखर्जी (सिविल) अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टरों के भरपूर प्रयासों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के कारणों को लेकर अभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है। शुरुआती पुलिस जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, नानक राम भुर्जी पिछले काफी समय से अवसाद (डिप्रेशन) से जूझ रहे थे और अक्सर विधायक निवास परिसर के आसपास घूमते देखे जाते थे। 68 वर्षीय नानक राम भुर्जी उत्तर प्रदेश राजनीति में एक जाना-माना चेहरा रहे हैं। वह राज्य सरकार में पूर्व राज्यमंत्री के पद पर सेवाएं दे चुके थे और वर्तमान में भाजपा के ओबीसी मोर्चा में प्रदेश मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बिजनौर और आसपास के क्षेत्रों में उनका अच्छा-खासा जनाधार था। उनकी मौत की खबर फैलते ही भाजपा संगठन और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, उनके समर्थक और शुभचिंतक सिविल अस्पताल के बाहर जमा होने लगे।

लिफ्ट मांगकर स्कूटी पर बैठे बदमाश ने दुकानदार की जेब काटकर 46,500 रुपये चुरा लिए

जानकीपुरम इलाके में लिफ्ट मांगकर बैठे बदमाश ने स्कूटी सवार दुकानदार अजयकांत कटियार की जेब काटकर 46,500 रुपये चुरा लिए। आरोपी सड़क के दूसरी ओर खड़े बाइक सवार साथी के साथ भाग गया। जानकीपुरम सेक्टर-3 निवासी अजयकांत कटियार के अनुसार, 60 फीटा रोड पर उनकी किराने की दुकान है। सोमवार दोपहर वह स्कूटी से रकाबगंज खरीदारी करने जा रहे थे। 60 फीट रोड पर एक युवक ने उनसे लिफ्ट मांगी। गोकुल मिष्ठान के सामने युवक ने स्कूटी रोकने को कहा और उतरते समय उनकी जेब काट ली। उतरते वक्त उसका पैर स्कूटी के फुटरेस्ट में फंस गया, जिससे वह सड़क पर गिर पड़ा। इस दौरान उसके पास मौजूद चोरी के 13500 रुपये सड़क पर गिरकर बिखर गए। उन्होंने अपनी जेब देखी तो वह कटी हुई थी और उसमें रखे 60000 रुपये गायब थे। शोर मचाने पर बदमाश सड़क पार खड़े अपने बाइक सवार साथी के साथ भाग निकला। इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि चोरी की एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिये आरोपियों की तलाश कर रही है।लखनऊ के जानकीपुरम में लिफ्ट मांगकर स्कूटी पर बैठे बदमाश ने दुकानदार की जेब काटकर 46,500 रुपये चुरा लिए। भागते समय कुछ नकदी सड़क पर गिर गई। आरोपी साथी के साथ फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर अखिलेश पर हुए हमलावर

यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जिले के प्रभारी मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को अंबेडकरनगर आगमन पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि छात्र आंदोलन के बाद राहुल गांधी की राजनीतिक ताकत बढ़ी है जबकि अखिलेश यादव की पकड़ कमजोर हो रही है। इससे विपक्ष के भीतर घबराहट का माहौल है। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में राजभर ने कहा कि राहुल गांधी के सक्रिय होने से विपक्षी दल असहज हैं जबकि अखिलेश यादव केवल मुख्यमंत्री बनने की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि यादव और मुस्लिम समाज का एक वर्ग भी समाजवादी पार्टी से दूरी बना रहा है। उन्होंने कहा कि यदि संसद सुचारू रूप से चलने दी जाए तो सपा और कांग्रेस दोनों की वास्तविकता जनता के सामने आ जाएगी।उन्होंने कहा कि यदि संसद सुचारू रूप से चलने दी जाए तो सपा और कांग्रेस दोनों की वास्तविकता जनता के सामने आ जाएगी।

बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 15 सीनियर आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मंगलवार दोपहर पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। कानून-व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के इरादे से शासन ने 15 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इस बड़े बदलाव में राजधानी लखनऊ और प्रयागराज जैसे अहम जिलों के पुलिस कमिश्नर भी बदल दिए गए हैं। तेजतर्रार IPS अफसर तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। शासन द्वारा जारी की गई नई तबादला सूची के अनुसार, वाराणसी के ADG जोन पीयूष मोर्डिया को अब प्रयागराज का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वह प्रयागराज में कानून-व्यवस्था की कमान संभालेंगे। वहीं तकनीकी सेवाएं में ADG के पद पर तैनात नवीन अरोड़ा को अब वाराणसी का नया ADG जोन बनाकर भेजा गया है। इन बड़े बदलावों के अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई और अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। वरिष्ठ IPS अधिकारी अशोक मुथा को डीजी फायर सर्विस बनाया गया है। वहीं लॉजिस्टिक विभाग में ADG के पद पर कार्यरत राम कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। राम कुमार को अब गोरखपुर का ADG जोन नियुक्त किया गया है। सरकार के इस कदम को आगामी चुनौतियों और पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह बनाने की दिशा में एक अहम फैसला माना जा रहा है।सूत्रों के मुताबिक 25 जुलाई को प्रयागराज में नीट पेपर लीक के विरोध में हुए भारी छात्र प्रदर्शन और हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री खासे नाराज थे। इसका सीधा असर इन तबादलों में देखने को मिला है। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर जोगेंद्र कुमार को उनके पद से हटाकर पीटीएस मुरादाबाद का आईजी बना दिया गया है। इसके साथ ही छात्र आंदोलन के दौरान खुफिया तंत्र की नाकामी को देखते हुए लंबे समय से एडीजी इंटेलिजेंस के पद पर तैनात भगवान स्वरूप श्रीवास्तव को भी हटा दिया गया है। उन्हें अब एडीजी तकनीकी सेवाएं की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के शाही स्नान को लेकर हुए विवाद के समय गृह विभाग के सचिव आईपीएस मोहित गुप्ता काफी चर्चा में आए थे। उस मामले में उनकी भूमिका पर कई सवाल उठे थे। अब सरकार ने उन्हें गृह विभाग से हटाकर आईजी भ्रष्टाचार निवारण संगठन भेज दिया है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कड़ा रुख अपनाया, तीन जिम्मेदार अफसर हटाए गए

कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पहली ही बारिश के बाद सड़क की ऊपरी परत उखड़ने और धंसने का मामला सामने आने के बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने सख्त कार्रवाई की है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद NHAI ने तत्काल संज्ञान लेते हुए न केवल क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराई, बल्कि परियोजना की निगरानी में लापरवाही बरतने वाले तीन अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। इन अधिकारियों को परियोजना से हटाने के साथ-साथ अगले दो वर्षों तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और NHAI की किसी भी परियोजना में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है।जानकारी के अनुसार, एक्सप्रेसवे के किलोमीटर-64 के पास सड़क की सतह पर स्लिपेज और बिटुमिनस परत के उखड़ने की शिकायत सामने आई थी। पहली ही बारिश में सड़क की हालत बिगड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठने लगे। इसके बाद 26 जुलाई को NHAI और निर्माण एजेंसी की संयुक्त तकनीकी टीम ने मौके पर पहुंचकर विस्तृत निरीक्षण किया।जांच में यह स्पष्ट हुआ कि समस्या सड़क की केवल ऊपरी बिटुमिनस परत तक सीमित थी। तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार, लगातार हो रही बारिश, भारी यातायात और सड़क के जोड़ों से पानी के रिसाव के कारण सतह पर स्लिपेज हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि पुल या एक्सप्रेसवे के मुख्य ढांचे, नींव और संरचनात्मक मजबूती पर इसका कोई असर नहीं पाया गया। अधिकारियों ने बताया कि सड़क की मूल संरचना पूरी तरह सुरक्षित है और किसी प्रकार का संरचनात्मक खतरा नहीं है।निरीक्षण के तुरंत बाद NHAI ने क्षतिग्रस्त हिस्से की उखड़ी हुई परत हटाकर नई बिटुमिनस लेयर बिछा दी। साथ ही भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने, इसके लिए सड़क के जोड़ों की सीलिंग मजबूत करने और जल निकासी (ड्रेनेज) व्यवस्था में भी सुधार किया गया है। प्राधिकरण का कहना है कि मानसून के दौरान सड़क की लगातार निगरानी की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त तकनीकी उपाय भी अपनाए जाएंगे।मामले में जवाबदेही तय करते हुए NHAI ने निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विवेक कुमार गुप्ता, इंडिपेंडेंट इंजीनियर के टीम लीडर सुरेंद्र कुमार और रेसिडेंट इंजीनियर यतेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से परियोजना से हटा दिया है। तीनों अधिकारियों को आगामी दो वर्षों तक MoRTH और NHAI की किसी भी परियोजना में कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। NHAI ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और भविष्य में भी लापरवाही पाए जाने पर इसी तरह की कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

युवाओं को मिलेगा रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण, डीएम ने दिए निर्देश

उन्नाव में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने मंगलवार को विकास भवन सभागार में जिला कौशल समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने जनपद में संचालित विभिन्न कौशल विकास योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। जिलाधिकारी ने अधिकारियों और प्रशिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए कि युवाओं को केवल औपचारिक प्रशिक्षण देने के बजाय गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करना है। बैठक में जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों से प्रत्येक विषय में दिए जा रहे प्रशिक्षण, प्रशिक्षित युवाओं की संख्या और प्रशिक्षण के बाद हुए रोजगार या प्लेसमेंट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने जोर दिया कि प्रशिक्षण का उद्देश्य तभी सफल माना जाएगा, जब इसका सकारात्मक प्रभाव जमीन पर दिखे और प्रशिक्षित युवाओं के कौशल एवं व्यक्तित्व में स्पष्ट सुधार नजर आए। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों और प्रशिक्षण एजेंसियों को निर्देशित किया कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय उद्योगों और बाजार की जरूरतों के अनुरूप संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि युवाओं को ऐसे कौशल से जोड़ना आवश्यक है, जिनकी रोजगार बाजार में अधिक मांग हो, ताकि उन्हें नौकरी और स्वरोजगार स्थापित करने में मदद मिल सके।

श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन औषधि प्रशासन विभाग ने अभियान शुरू किया

उन्नाव में श्रावण मास और कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने व्यापक जांच अभियान शुरू किया है। विभाग ने एक महीने का रोडमैप तैयार किया है, जिसके तहत लगातार निरीक्षण किए जाएंगे।इस अभियान के तहत जिले भर में 200 से अधिक होटल, ढाबों, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। हाईवे और प्रमुख मार्गों पर स्थित प्रतिष्ठानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएस एक्ट) के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की सहायक आयुक्त (खाद्य) प्रियंका ने बताया कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए विभाग ने अलग-अलग टीमें गठित की हैं। इन टीमों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी कांवड़ यात्री या उपभोक्ता को अशुद्ध अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थ न मिलें। निरीक्षण के दौरान खाद्य प्रतिष्ठानों पर विभाग का टोल-फ्री नंबर भी चस्पा कराया जा रहा है। इससे उपभोक्ता सीधे विभाग तक अपनी शिकायतें पहुंचा सकेंगे। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रियंका ने स्पष्ट किया कि जिन होटलों और ढाबों में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन परोसा जाता है, उन्हें एफएसएसएआई के सभी नियमों का पालन करना होगा। इसके तहत वेज और नॉन-वेज भोजन के लिए अलग रसोई, अलग बर्तन और अलग-अलग व्यवस्था अनिवार्य है। यदि निरीक्षण या शिकायत के आधार पर यह पाया गया कि दोनों प्रकार के भोजन एक ही बर्तन या एक ही व्यवस्था में तैयार किए जा रहे हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में हुए निरीक्षण के दौरान जनता ढाबा में कई कमियां पाई गई थीं। इन कमियों के आधार पर संचालक को नोटिस जारी करते हुए प्रतिष्ठान को अग्रिम आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।

चकमा देकर भागने की कोशिश, भागते समय कटीले तारों में फंसकर घायल

उन्नाव जिले के बीघापुर/बारासगवर थाना क्षेत्र में चोरी के माल के साथ पकड़े गए एक शातिर आरोपी ने पुलिस को चकमा देकर भागने की कोशिश की। हालांकि, भागते समय खेत में लगे कटीले तारों में फंसकर वह बुरी तरह घायल हो गया। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उसे तुरंत दबोच लिया और प्राथमिक उपचार कराने के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नाबालिगों से चोरी का माल खरीदता था। जानकारी के अनुसार, बारासगवर थाना क्षेत्र के मनीखेड़ा निवासी आशीष कुमार लंबे समय से चोरी का माल खरीदने और बेचने के अवैध कारोबार में लिप्त था। करीब 01 सप्ताह पहले जगतखेड़ा निवासी सचिन के बंद घर से पंपिंग सेट और अन्य कीमती सामान चोरी हो गया था। पीड़ित की शिकायत और मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने आशीष को चोरी के पंपिंग सेट के साथ गिरफ्तार किया था। इसी दौरान आरोपी पुलिसकर्मियों को चकमा देकर हाथ छुड़ाकर भागने लगा, लेकिन पीछा किए जाने पर खेत की बाड़ में लगे लोहे के कटीले तारों में उलझकर घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाकर उपचार कराया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्रनाथ मिश्र ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी आशीष ने खुलासा किया कि वह क्षेत्र के 03 नाबालिग लड़कों से चोरी का सामान कौड़ियों के भाव खरीदता था। आरोपी के बयान के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों बाल अपचारियों को हिरासत में ले लिया। कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जबकि मुख्य आरोपी आशीष को जेल भेज दिया गया है।

गुरु पूर्णिमा मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने किया निरीक्षण

उन्नाव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मां चंद्रिका देवी धाम बक्सर घाट पर लगने वाले मेले और गंगा स्नान की तैयारियां तेज हो गई हैं। मंगलवार दोपहर करीब ढाई बजे जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह के साथ बक्सर घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, बैरिकेडिंग, शौचालय और महिलाओं के चेंजिंग रूम सहित श्रद्धालुओं की सुविधाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान और मां चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय पर पूरी करने और किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी बीघापुर को घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया, ताकि रात में श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। उन्होंने महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम समय पर तैयार कराने और शौचालयों की नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने को कहा। इसके अतिरिक्त, घाटों और मेला परिसर में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया।

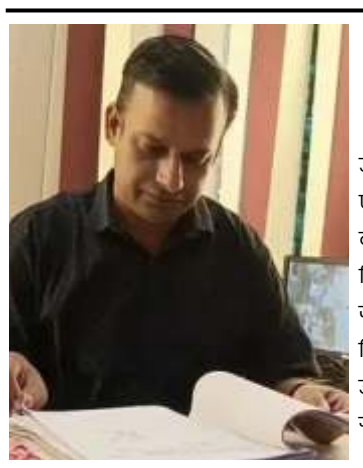

उन्नाव में हर सप्ताह चलेगा बेसहारा लोगों के लिए रेस्क्यू अभियान

उन्नाव जिला प्रशासन ने बेसहारा बच्चों, वृद्धजनों और असहाय लोगों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक विशेष साप्ताहिक रेस्क्यू अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत हर सप्ताह संयुक्त टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें संबंधित संस्थाओं या परिजनों तक पहुंचाएंगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे ने मंगलवार को बताया कि यह अभियान माननीय हाईकोर्ट में दाखिल ज्योति राजपूत प्रकरण के अनुपालन में प्रदेश के सभी जनपदों में चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क किनारे रहने वाले गरीब, असहाय बच्चों, निराश्रित वृद्धजनों और बेघर लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना है। इस कार्य के लिए जनपद स्तर पर 11 सदस्यीय रेस्क्यू टीम का गठन किया गया है। मंगलवार को हुई टीम की बैठक में अभियान की रूपरेखा तय की गई। निर्णय लिया गया कि उन्नाव में प्रत्येक सप्ताह नियमित रूप से रेस्क्यू अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान मिलने वाले बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों और अन्य जरूरतमंद लोगों को उनकी परिस्थिति के अनुसार आश्रय गृह, बाल संरक्षण संस्थान या उनके परिवार के साथ पुनर्वासित किया जाएगा। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जानकारी दी कि 1 जनवरी 2026 से 30 जून 2026 के बीच जनपद में 150 से अधिक बच्चों का रेस्क्यू किया जा चुका है। इनमें से कई बच्चों को बाल संरक्षण संस्थाओं में भेजा गया, जबकि कई बच्चों का उनके माता-पिता और परिजनों से संपर्क कराकर सुरक्षित पुनर्वास कराया गया। आगामी अभियान में वन स्टॉप सेंटर, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभाग भी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। सभी विभाग आपसी समन्वय से जरूरतमंद लोगों की पहचान कर उन्हें आवश्यक सहायता और संरक्षण उपलब्ध कराएंगे।

मेरठ के तीन दोस्तों की अनोखी कांवड़ यात्रा बनी मिसाल

मुस्लिम युवक शाकिर ने दिया भाईचारे और इंसानियत का संदेश

सावन के पवित्र महीने में हरिद्वार से गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करते हैं।इसी बीच मेरठ के तीन दोस्तों—मिंटू, गौरव और मोहम्मद शाकिर—की 201 लीटर गंगाजल वाली कांवड़ यात्रा चर्चा का विषय बन गई है।यह यात्रा धार्मिक आस्था के साथ-साथ सामाजिक सद्भाव, भाईचारे और गंगा-जमुनी तहजीब का संदेश भी दे रही है।

उत्तर प्रदेश में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ जारी है। हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे लाखों शिवभक्तों के बीच इस बार मुजफ्फरनगर से गुजर रही एक विशेष कांवड़ यात्रा लोगों के आकर्षण का केंद्र बन गई है। इसकी वजह सिर्फ 201 लीटर गंगाजल से सजी विशाल कांवड़ नहीं, बल्कि उसे लेकर चल रहे तीन दोस्तों की दोस्ती और सामाजिक सद्भाव का संदेश है। मेरठ के रहने वाले मिंटू, गौरव और मोहम्मद शाकिर की यह यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।तीनों दोस्त हरिद्वार से 201 लीटर गंगाजल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। उनके कंधों पर सजी विशाल कांवड़ और जुबान पर गूंजते "हर-हर महादेव" तथा "बम-बम भोले" के जयकारे राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। यात्रा के दौरान जहां श्रद्धालु उनकी आस्था को नमन कर रहे हैं, वहीं उनकी दोस्ती और आपसी विश्वास की भी सराहना कर रहे हैं।इस यात्रा में सबसे अधिक चर्चा मोहम्मद शाकिर की हो रही है। मुस्लिम समुदाय से होने के बावजूद वह पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ अपने दोस्तों के साथ कांवड़ यात्रा में शामिल हैं। सिर पर टोपी और कंधे पर कांवड़ का भार उठाए शाकिर न केवल अपने साथियों का सहयोग कर रहे हैं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले अन्य कांवड़ियों की मदद भी करते दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में प्रेम, भाईचारे और इंसानियत का संदेश देना भी है।मोहम्मद शाकिर ने कहा कि उनका संदेश साफ है—"जात-पात छोड़ो, इंसानियत जोड़ो।" उनके अनुसार इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और हर व्यक्ति की पहली पहचान एक इंसान के रूप में होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब वह कांवड़ यात्रा में शामिल हुए हैं। इससे पहले भी वह अपने दोस्त मिंटू के साथ 101 लीटर गंगाजल की कांवड़ ला चुके हैं। इस बार उनके साथ गौरव भी जुड़े हैं और तीनों मिलकर 201 लीटर गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने जा रहे हैं।मिंटू ने बताया कि हरिद्वार से लाया गया यह पवित्र गंगाजल मेरठ के नगौड़ी गांव स्थित शिव मंदिर में भगवान शिव को अर्पित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे बड़ी कामना समाज में प्रेम, सौहार्द और भाईचारा बनाए रखना है। उनका मानना है कि धर्म अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन दोस्ती, विश्वास और इंसानियत का रिश्ता सबसे ऊपर होता है।रास्ते में इस अनोखी कांवड़ यात्रा को देखने वाले श्रद्धालु भी तीनों दोस्तों की जमकर सराहना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसे उदाहरण समाज में सकारात्मक संदेश देते हैं और यह दिखाते हैं कि आस्था और इंसानियत साथ-साथ चल सकती हैं। हर-हर महादेव के जयघोष के बीच आगे बढ़ रही मिंटू, गौरव और मोहम्मद शाकिर की यह यात्रा केवल गंगाजल लेकर नहीं चल रही, बल्कि सामाजिक सद्भाव, आपसी सम्मान और गंगा-जमुनी तहजीब की जीवंत मिसाल भी पेश कर रही है।

ज्वैलरी कारोबारी के 10 साल के पोते का मिला शव ,पड़ोसी टीचर गिरफ्तार

यूपी के गोरखपुर से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक बड़े ज्वैलरी कारोबारी के 10 साल के पोते का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बच्चा कल स्कूल से घर लौटने के बाद खेलने के लिए बाहर निकला था और फिर लापता हो गया था। गोरखपुर में एक बड़े ज्वैलरी कारोबारी के 10 साल के पोते के कल (सोमवार) रहस्यमय तरीके से लापता होने से सनसनी फैल गई थी। स्कूल से घर लौटने के बाद मासूम खेलने निकला था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी साइकिल और चप्पल मिली, जबकि बच्चा गायब हो गया था। अपहरण की आशंका के बीच पुलिस की पांच टीमें जांच में जुटी हुई थीं, आज उस मासूम का शव पड़ोसी के घर में मिला। पुलिस ने पड़ोसी कंप्यूटर टीचर सर्वेश भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसने क्यों हत्या की इसकी पूछताछ पुलिस कर रही है। घटना गोरखपुर के खजनी कस्बे की है, जहां ज्वैलरी कारोबारी लक्ष्मी नारायण वर्मा के 10 वर्षीय पोते वैभव के कल अचानक लापता होने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। चौथी कक्षा में पढ़ने वाला वैभव सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे स्कूल से घर लौटा। यूनिफॉर्म बदलने के बाद वह साइकिल लेकर खेलने निकल गया। करीब आधे घंटे बाद एक पड़ोसी ने परिवार को बताया कि वैभव की साइकिल घर के पीछे लावारिस हालत में पड़ी है। परिजन मौके पर पहुंचे तो बच्चा कहीं नहीं मिला। तलाश के दौरान साइकिल से करीब 100 मीटर दूर खाली खेत में उसकी एक चप्पल भी बरामद हुई। इसके बाद परिवार ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी थी। कल से सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया। सीसीटीवी फुटेज में दोपहर 2 बजकर 7 मिनट पर वैभव साइकिल से गली में जाता दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई।

रामनगरी में सावन मेले की अंतिम तैयारियां

गुरु पूर्णिमा और श्रावण मास की शुरुआत से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को मजबूत करने की तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन में किसी तरह की असुविधा नहीं होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि मंदिर में रामलला के दर्शन नियमित और व्यवस्थित तरीके से कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। महंत दिनेंद्र दास ने बताया कि सावन माह के दौरान आयोजित होने वाले झूला उत्सव की तैयारियां भी अंतिम चरण में हैं। परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी रामलला को चांदी के झूले पर विराजमान कर झुलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शासन और मंदिर प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। सावन झूला मेले के दौरान भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के सर्किल अधिकारी (सीओ) आशुतोष तिवारी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को नौ सेक्टरों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक सेक्टर में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावी बनी रहे। उन्होंने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल के साथ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात रहेंगी। इसके अलावा पूरे मेला क्षेत्र की निगरानी सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और कंट्रोल रूम के माध्यम से चौबीसों घंटे की जाएगी।

गाजीपुर में मुख्तार गैंग के शस्त्र लाइसेंसों की जांच रिकॉर्ड गायब मिलने पर 5 FIR दर्ज

उत्तर प्रदेश पुलिस ने कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी और उसके गैंग (IS-191) से जुड़े लोगों के शस्त्र लाइसेंसों की जांच में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के बाद गाजीपुर में 5 अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। पुलिस का दावा है कि जांच के दौरान कई शस्त्र लाइसेंसों की मूल पत्रावलियां और हथियारों के क्रय-विक्रय से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से गायब पाए गए। मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है। पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर STF द्वारा जुटाई गई सूचनाओं के आधार पर वाराणसी परिक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक ने गाजीपुर पुलिस को मुख्तार अंसारी, उसके परिजनों, गैंग के सदस्यों और सहयोगियों को जारी शस्त्र लाइसेंसों का फिजिकली सत्यापन कराने के निर्देश दिए थे। इस कार्रवाई के तहत कुल 43 लोगों के शस्त्र लाइसेंसों और उनसे जुड़े 80 से अधिक हथियारों का सत्यापन किया गया। जांच में पता चला कि कई मामलों में शस्त्र लाइसेंसों की मूल फाइलें और हथियारों के खरीद-बिक्री से जुड़े रिकॉर्ड गायब हैं। पुलिस के अनुसार, लाइसेंसधारकों ने तत्कालीन शस्त्र लिपिकों और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर अभिलेख गायब कराए, ताकि हथियारों की वास्तविक स्थिति छिपाई जा सके और उनके संभावित दुरुपयोग का पता न चल सके। एक मामले में फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने का भी खुलासा हुआ है। जांच के आधार पर गाजीपुर के कोतवाली और मुहम्मदाबाद थानों में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इनमें अफजाल अंसारी, अफसा बेगम, गैंग के सहयोगी मोहम्मद शाहिद तथा तत्कालीन शस्त्र लिपिकों और अन्य अधिकारियों को नामजद किया गया है। आरोपों में आपराधिक षड्यंत्र, सरकारी अभिलेख गायब कराने, फर्जी जानकारी देकर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने और आयुध अधिनियम के उल्लंघन जैसी धाराएं शामिल हैं।